

सितंबर 2023

## PRS के प्रमुख हाइलाइट्स

- **माइक्रोइकोनॉमिक विकास**
  - चालू खाता घाटा GDP का 1.1% पर
- **कानून एवं न्याय**
  - महिला आरक्षण अधिनियम 2023
  - चुनाव के लिये समिति का गठन
  - ई-कोर्ट चरण-III को मंजूरी
  - POCSO अधिनियम
  - FIR के ऑनलाइन पंजीकरण को सक्षम करना
- **वित्त**
  - वाणज्यिक बैंकों के नविश पोर्टफोलियो पर दशिया-नरिदेश
  - व्यक्तगित ऋणों के पुनर्भुगतान पर संपत्ति दस्तावेज़ जारी
  - ऐच्छिक और बड़े डफॉल्टर्स के प्रबंधन हेतु मसौदा नरिदेश
- **गृह मामले**
  - जेलों की स्थिति, इंफ्रास्ट्रक्चर और सुधारों पर स्थायी समिति की रिपोर्ट
- **उपभोक्ता मामले**
  - ई-कॉमर्स में डार्क पैटर्न को वनियमिति करने हेतु दशिया-नरिदेश
- **परविहन**
  - स्थायी समिति ने राष्ट्रीय अंतरदेशीय जलमार्ग पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की
  - भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम (Bharat NCAP)
  - फिटनेस प्रमाणपत्र की वैधता
- **पर्यटन**
  - भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण की कार्य प्रणाली पर रिपोर्ट
  - वशिष्ट पर्यटन और संभावित पर्यटन स्थलों के विकास पर स्थायी समिति की रिपोर्ट
- **ऊर्जा**
  - ऊर्जा भंडारण प्रणालियों को बढ़ावा देने हेतु रूपरेखा जारी
  - कैप्टिव बिजली उत्पादकों और उपयोगकर्ता संबंधी नयिमों में संशोधन
- **खनन**
  - खनन लीज़ और कंपोज़िट लाइसेंस की नीलामी के नयिमों में संशोधन
- **पर्यावरण**
  - वसितारति नरिमाता उत्तरदायित्व नयिम अधिसूचति
- **शक्तिषा**
  - उच्च शक्तिषा में NEP के कार्यान्वयन पर रिपोर्ट
- **श्रम एवं रोज़गार**
  - स्थायी समितिद्वारा कर्मचारी राज्य बीमा नगिम पर रिपोर्ट प्रस्तुत

### माइक्रोइकोनॉमिक विकास

#### चालू खाता घाटा GDP का 1.1% पर

- **चालू खाता:**
  - वर्ष 2023-24 की पहली तमिाही (अप्रैल-जून) में **चालू खाते** में 9.2 बलियिन अमेरकी डॉलर (GDP का 1.1%) का घाटा दर्ज कयिा

गया, जो कविर्ष 2022-23 की इसी तमिही के 17.9 बलियिन अमेरकी डॉलर (GDP का 2.1%) के घाटे से काफ़ी कम है।

• इसी अवर्ध में व्वापारक व्वापार घाटा 63.1 बलियिन अमेरकी डॉलर से घटकर 56.6 बलियिन अमेरकी डॉलर हो गया।

• वर्ष 2022-23 की चौथी तमिही (जनवरी-मार्च) में **चालू खाता घाटा 1.3 बलियिन अमेरकी डॉलर (GDP का 0.2%)** था।

#### ■ पूंजी खाता:

• **पूंजी खाते** में वर्ष 2023-24 की पहली तमिही में 34.4 बलियिन अमेरकी डॉलर का शुद्ध प्रवाह दर्ज कया गया, जबकविर्ष 2022-23 की इसी तमिही में 22.1 बलियिन अमेरकी डॉलर का शुद्ध प्रवाह दर्ज कया गया था।

• **वदिशी पोर्टफोलियो नविश** ने वर्ष 2023-24 की पहली तमिही में 15.7 बलियिन अमेरकी डॉलर का शुद्ध प्रवाह दर्ज कया, जबकविर्ष 2022-23 की पहली तमिही में 14.6 बलियिन अमेरकी डॉलर का शुद्ध बहरिवाह दर्ज कया गया था।

• वर्ष 2022-23 की चौथी तमिही में **पूंजी खाते में 6.5 बलियिन अमेरकी डॉलर का शुद्ध प्रवाह दर्ज कया गया था।**

#### ■ वदिशी मुद्रा भंडार:

• वर्ष 2023-24 की पहली तमिही में इसमें 24.4 बलियिन अमेरकी डॉलर की वृद्धि हुई, जो **वर्ष 2022 की समान तमिही में हुई 4.6 बलियिन अमेरकी डॉलर की वृद्धि से काफ़ी अधिक है।**

## कानून एवं न्याय

### महिला आरक्षण वधियक 2023

■ संसद का वशिष सत्र 18 सतिंबर, 2023 से 21 सतिंबर, 2023 तक चार बैठकों के साथ आयोजति कया गया था।

■ इस सत्र के दौरान **महिला आरक्षण वधियक 2023 (128वाँ संवैधानिक संशोधन वधियक) अधनियिम** पारति कया गया।

• यह वधियक लोकसभा, राज्य वधिानसभाओं और दलिली वधिानसभा में महिलाओं के लयि एक-तहिाई सीटें आरक्षति करता है।

#### वधियक की मुख्य वशिषताएँ:

■ इस वधियक के लागू होने के बाद आयोजति जनगणना के प्रकाशन के बाद यह आरक्षण प्रभावी होगा।

■ जनगणना के आधार पर महिलाओं के लयि सीटें आरक्षति करने हेतु परसिमन कया जाएगा। आरक्षण 15 वर्ष की अवर्ध के लयि प्रदान कया जाएगा।

■ हालाँकि यह **संसद** द्वारा बनाए गए कानून द्वारा नरिधारति तथितिक जारी रहेगा।

■ हर परसिमन के बाद महिलाओं के लयि आरक्षति सीटों को रोटेट कया जाएगा, जैसा कि संसद द्वारा बनाए गए कानून द्वारा नरिधारति कया जाएगा।

#### वचिारणीय मुद्दे:

■ वधिानमंडलों में महिलाओं के लयि सीटों के आरक्षण के मुद्दे की जाँच तीन दृष्टिकोणों से की जा सकती है:

• कया महिलाओं के लयि आरक्षण की नीति उनके सशक्तीकरण हेतु एक प्रभावी साधन के रूप में कार्य कर सकती है।

• कया वधिानमंडलों में महिलाओं का प्रतनिधित्व बढ़ाने के वैकल्पिक तरीके संभव हैं।

• कया वधियक में आरक्षण की प्रस्तावति पद्धति को लेकर कोई समस्या है।

■ राजनीतिक दलों और दोहरे सदस्य नरिवाचन क्षेत्रों में आरक्षण के पक्ष और वपिक्ष:

	लाभ	हानि
राजनीतिक दल	<ul style="list-style-type: none"><li>मतदाताओं को अधिक लोकतांत्रिक विकल्प प्रदान करना।</li><li>स्थानीय राजनीतिक एवं सामाजिक कारकों के आधार पर पार्टियों को उम्मीदवारों और नरिवाचन क्षेत्रों के चयन में अधिक सक्रम बनाना।</li><li>जनि क्षेत्रों में इसका चुनावी लाभ होगा वहाँ अल्पसंख्यक समुदाय की महिलाओं को नामांकति कया जा सकता है।</li><li>संसद में महिलाओं की संख्या में लचीलेपन की अनुमति देना।</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि बड़ी संख्या में महिलाएँ नरिवाचति होंगी।</li><li>राजनीतिक दल महिला उम्मीदवारों को उन नरिवाचन क्षेत्रों में नयिकृत कर सकते हैं जहाँ वे कमज़ोर हैं।</li><li>यदि किसी शक्तीशाली पुरुष उम्मीदवार के स्थान पर किसी महिला को वशिष महत्त्व दिया जाएगा तो इस पर नाराज़गी हो सकती है।</li></ul>
दोहरे सदस्य नरिवाचन क्षेत्र	<ul style="list-style-type: none"><li>मतदाताओं के लयि लोकतांत्रिक विकल्प कम नहीं होते।</li><li>पुरुष उम्मीदवारों के साथ कोई भेदभाव नहीं करता।</li><li>सदस्यों के लयि उन नरिवाचन क्षेत्रों का पोषण करना आसान हो सकता है जनिकी औसत आबादी लगभग 2.5 मलियन है।</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>मौजूदा सदस्यों को अपना राजनीतिक आधार साझा करने की आवश्यकता हो सकती है।</li><li>महिलाएँ गौण या सहायक बन सकती हैं।</li><li>33% महिलाओं के मानदंड को पूरा करने के लयि आधी सीटों पर दोहरे सदस्य नरिवाचन क्षेत्र होने की आवश्यकता है। इससे संसद सदस्यों (सांसदों) की कुल संख्या में 50% की वृद्धि होगी,</li></ul>

- संसद और राज्य वधिानसभाओं में महिलाओं के लयि सीटें आरकषति करने के लयि संवधिान में संशोधन करने वाले वधिियक्वर्ष 1996, 1998, 1999 और 2008 में पेश कयि गए हैं।
  - पहले के तीन वधिियक संबंधति लोकसभाओं के वधििटन के साथ समाप्त हो गए।
  - वर्ष 2008 का वधिियक [राज्यसभा](#) में पेश कयिा गया तथा पारति हुआ लेकनि 15वीं लोकसभा के भंग होने के साथ ही यह भी समाप्त हो गया।

वर्ष 2008 और वर्ष 2023 में पेश कयि गए वधिियक के बीच मुख्य परविर्रतन:

	राज्यसभा द्वारा पारति होने के बाद वर्ष 2008 में वर्ष 2023 में पेश कयिा गया वधिियक
लोकसभा में आरकषण	प्रत्येक राज्य/केंद्रशासति प्रदेश में एक-तहिाई महिलाओं के लयि एक-तहिाई सीटें आरकषति की जाएंगी।
सीटों का क्रमकि आवंटन	संसद/वधिानसभा के लयि प्रत्येक आम चुनाव के बाद प्रत्येक <a href="#">प्रसिमान</a> अभ्यास के बाद आरकषति सीटों आरकषति सीटों का क्रमकि आवंटन कयिा जाएगा। को आवंटति कयिा जाएगा।

- वशिष सत्र के दौरान चर्चा के लयि रखे गए अन्य वधिियक:
  - नरिसन एवं संशोधन वधिियक, 2022
  - [अंतरराज्यीय नदी जल वविाद \(संशोधन\) वधिियक, 2019](#)
  - अधविकता (संशोधन) वधिियक, 2023
  - प्रेस और पत्रकिा पंजीकरण (संशोधन) वधिियक, 2023

## चुनाव के लयि समति किा गठन

- परचिय:
  - केंद्र सरकार ने [एक साथ चुनाव](#) कराने के संबंध में जाँच तथा सफिररशिं करने के लयि एक उच्च स्तरीय समति किा गठन कयिा।
    - एक साथ चुनाव से तात्पर्य एक ही समय में होने वाले लोकसभा, राज्य वधिानसभाओं और स्थानीय नकिायों के चुनावों से है।
- समति किे सदस्य:
  - समति किे अध्यक्ष के रूप में पूर्व राष्ट्रपति और सात सदस्य होंगे। समति किे सदस्यों में शामिल हैं:
    - गृह राज्य मंत्री।
    - [15वें वति्त आयोग](#) का पूर्व अध्यक्ष।
- संदर्भ की शर्तें:
  - समति लोकसभा, राज्य वधिानसभाओं और स्थानीय नकिायों के लयि एक साथ चुनाव कराने से संबंधति कानूनों एवं वनियिमों की समीकष करेगी तथा उनमें बदलाव का सुझाव देगी।
    - इन बदलावों में संवधिान के [जन प्रतनिधितिव अधनियिम, 1950](#) और [जन प्रतनिधितिव अधनियिम, 1951](#) में संशोधन शामिल हो सकते हैं।
  - समति यह भी जाँच करेगी कि कयिा संवैधानकि संशोधनों के लयि राज्यों के समर्थन की आवश्यकता होगी।
  - समति किे अन्य कार्य:
    - चुनावों को समकालकि बनाने के लयि एक रूपरेखा का सुझाव देना।
    - एक साथ चुनाव चक्र की नरिररता सुनशिचति करने के लयि सुरकषा उपायों की सफिररशि करना।
    - लॉजसि्टिकस और क्रमचारयिों की आवश्यकताओं की समीकषा करना।
    - वभिनिन चुनावों में मतदाताओं के लयि एक ही मतदाता सूची एवं पहचान पत्र के उपयोग के तौर-तरीकों पर सुझाव देना।

## ई-कोर्ट चरण-III को मंजूरी

केंद्रीय मंत्रमिंडल ने वर्ष 2023 से 2027 तक [केंद्र प्रायोजति योजनाओं](#) के रूप में [ई-कोर्ट परयिोजना](#) के तीसरे चरण को मंजूरी दी।

- ई-कोर्ट परयिोजना:
  - भारतीय न्यायपालकिा को डिजिटल रूप से सकषम बनाने के लयि वर्ष 2007 में ई-कोर्ट परयिोजना शुरू की गई थी। इस योजना का चरण-II वर्ष 2023 में समाप्त हुआ।
  - इस योजना के चरण-I में बड़ी संख्या में ज़िला न्यायालयों का कंप्यूटरीकरण कयिा गया।
  - इसके अलावा इस योजना के दूसरे चरण का उद्देश्य नागरिकों को स्थानीय भाषाओं में सुलभ वेबसाइट जैसी सेवा वतिरण प्रदान करना है।
- चरण-III का उद्देश्य:
  - [ई-सेवा \(eSewa\) केंद्रों](#) के माध्यम से प्रौद्योगिकी पहुँच के बिना नागरिकों को न्यायकि सेवाएँ प्रदान करना।

- कहीं से भी न्यायालय शुल्क और जुर्माने का भुगतान संभव बनाना ।
- न्यायालय द्वारा पेपर-आधारित फाइलिंग पर निर्भरता को कम करना ।
- **बजटीय परियोजना का लगभग 28% व्यय स्कैनिंग, डिजिटलीकरण और केस रिकॉर्ड के डिजिटल संरक्षण पर**, जबकि लगभग 17% व्यय क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पर होने का अनुमान है ।

## POCSO अधिनियम

- महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने लोकसभा को सूचित किया है **क्यों अपराधों से बच्चों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम, 2012 बच्चों को यौन शोषण से बचाने के लिये सरकार द्वारा बनाए गए महत्वपूर्ण कानूनों में से एक है ।**
- **यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (POCSO) अधिनियम** के तहत **18 वर्ष से कम उम्र के किसी भी व्यक्ति को बच्चा माना जाता है ।** यह अधिनियम किसी बच्चे की सहमति के बावजूद उसके साथ यौन संबंधों को अपराध मानता है ।

## आयोग की मुख्य टिप्पणियाँ और सफारिशें:

- **सहमति की उम्र:** आयोग ने पोक्सो अधिनियम के तहत सहमति की उम्र को घटाकर 16 वर्ष करने का वरिध कया ।
- **16 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चे:** आयोग का कहना है कि अपराध के समय बच्चा 16 वर्ष या उससे अधिक का होने पर आरोपी को कम सज़ा दी जा सकती है । इसे पूरा करने के लिये कुछ मानदंडों की आवश्यकता होगी । इसमें नमिनलखिति शामिल हैं:
- विशेष अदालत इस बात से संतुष्ट है कि आरोपी और बच्चे के बीच घनिष्ठ संबंध थे ।
- बच्चे की मौन स्वीकृति ।
- आरोपी और बच्चे की उम्र में तीन साल से ज़्यादा का अंतर नहीं होना चाहिये ।
- आरोपी का कोई अपराधिक इतिहास नहीं हो ।
- अनुचित प्रभाव, बल या हिसा जैसे कारक मौजूद न हों ।
- **भारतीय दंड संहिता (IPC):** वर्तमान में IPC के तहत पति और उसकी पत्नी ( 18 वर्ष से कम उम्र) के बीच सहमति से यौन संबंध बलात्कार की श्रेणी में आता है । आयोग ने कहा कि IPC में संशोधन के बिना कश्शियों के रोमांटिक रश्शितों (Romantic Relationship) को राहत देने के लिये केवल **POCSO अधिनियम** में संशोधन करना अर्थहीन होगा । इसलिये आयोग ने IPC में उपयुक्त संशोधन का सुझाव दया ।

## FIR के ऑनलाइन पंजीकरण को सक्षम करना

- वधिआयोग ने "**प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR)** का ऑनलाइन पंजीकरण सुनिश्चित करने के लिये **आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973** की धारा 154 में संशोधन" पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की ।
- आयोग ने कहा कि दिल्ली, राजस्थान और उत्तर प्रदेश सहित आठ राज्यों ने ई-FIR के पंजीकरण को लागू कया है ।
- इसके अलावा नागरिक साइबर अपराध के संबंध में ऑनलाइन शकियात दर्ज कर सकते हैं ।
- आयोग ने ई-FIR के चरणबद्ध कार्यान्वयन की सफारिश की ।
- इसने उन सभी संज्जेय अपराधों के लिये **ई-FIR सुनिश्चित** करने की सफारिश की, जहाँ आरोपी के संबंध जानकारी ज्ञात नहीं है और ज्ञात आरोपी के मामले में **संज्जेय अपराधों में तीन वर्ष तक की कैद** की सज़ा हो सकती है ।
- आयोग ने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि **ई-FIR दर्ज करते समय प्रदान कये गए डेटा से समझौता नहीं कया जाना चाहिये ।**

## वित्त

### वाणज्यिक बैंकों के नविश पोर्टफोलियो पर दशा-नरिदेश

- **भारतीय रज़िर्व बैंक (RBI)** ने RBI (वाणज्यिक बैंकों के नविश पोर्टफोलियो का वर्गीकरण, मूल्यांकन और संचालन) दशा-नरिदेश, 2023 जारी कया ।
  - यह फ्रेमवर्क 1 अपरैल, 2024 से क्शेत्तीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर सभी वाणज्यिक बैंकों पर लागू होगा ।
- **इसकी वशिषताओं में नमिनलखिति शामिल हैं:**
  - **नविश नीति फ्रेमवर्क:** बैंकों को अपने बोर्ड द्वारा अनुमोदित नविश नीति अपनानी होगी । नीति में नमिनलखिति शामिल होने चाहिये:
  - नविश मानदंड और नविश लेन-देन के माध्यम से प्राप्त कये जाने वाले उद्देश्य ।
  - प्रतभूतियाँ, जनिमें बैंक नविश कर सकते हैं ।
- **नविश का वर्गीकरण:** बैंकों के नविश पोर्टफोलियो को इसमें वर्गीकृत कया जाना चाहिये:
  - परपिक्वता तक धारति (परपिक्वता तक धारण करने के इरादे से अर्जति) प्रतभूतियाँ ।
  - बकिरी के लिये उपलब्ध (नकदी प्रवाह के साथ-साथ बकिरी हेतु अर्जति) प्रतभूतियाँ ।
  - लाभ और हानि के माध्यम से उचति मूल्य प्रतभूतियाँ (जो उपरोक्त दो श्रेणियों में नहीं आती हैं) ।
- **आंतरिक नयित्रण प्रणाली:** बैंकों के पास नविश हेतु लेन-देन के लिये एक मज़बूत आंतरिक नयित्रण तंत्र होना चाहिये । इसमें ये भी शामिल हैं:
  - नविश बही का आवधिक मलिन ।
  - पोर्टफोलियो का मूल्यांकन ।
  - प्रूडेंशियल और जोखमि सीमाओं की नगरानी ।

## व्यक्तिगत ऋणों के पुनर्भुगतान पर संपत्ति दस्तावेज़ जारी

- भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने व्यक्तिगत ऋणों के पुनर्भुगतान पर वनियमिति संस्थाओं (जैसे बैंक) द्वारा चल/अचल संपत्ति दस्तावेज़ जारी करने के नरिदेश जारी किये।
  - व्यक्तिगत ऋण में शक्ति ऋण, आवास ऋण और वृत्तीय संपत्तियों में नविश के लिये ऋण शामिल हैं।
- हालाँकि RBI द्वारा ऐसे दस्तावेज़ों को जारी करने के लिये अलग-अलग पद्धतियों का इस्तेमाल किया जाता है।
  - नरिदेशों के अनुसार, वनियमिति संस्थाओं को ऋण खाते के पूरण पुनर्भुगतान/नपिटान के बाद 30 दिनों के भीतर मूल संपत्ति दस्तावेज़ों को जारी करना होगा। वनियमिति इकाई के कारण होने वाली किसी भी देरी के मामले में उधारकर्त्ता को प्रत्येक दिन के लिये 5,000 रुपए का मुआवज़ा दिया जाएगा।

## ऐच्छिक और बड़े डफिल्टरों के प्रबंधन हेतु मसौदा नरिदेश

- भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने सार्वजनिक प्रतिक्रियाओं के लिये RBI (ऐच्छिक डफिल्टरों और बड़े डफिल्टरों का प्रबंधन) दशा-नरिदेश, 2023 का मसौदा जारी किया। मसौदा नरिदेशों में उधारदाताओं द्वारा किसी उधारकर्त्ता को जान-बूझकर चूक करने वाले के रूप में वर्गीकृत करने की प्रक्रिया प्रदान करने का प्रयास किया गया है।

प्रमुख वशिषताओं में नमिनलखिति शामिल है:

- ऐच्छिक या जान-बूझकर डफिल्टर बनना:** ऐच्छिक डफिल्टर का अर्थ है:
  - एक उधारकर्त्ता या गारंटर जिसने कम-से-कम 25 लाख रुपए का डफिल्टर जान-बूझकर किया हो या RBI द्वारा अधिसूचित किया गया हो।
  - डफिल्टर के समय जुड़े प्रमोटर और नदिशक, यदि डफिल्टर एक कंपनी है।
  - किसी इकाई (कंपनियों के अलावा) के मामलों के प्रबंधन के लिये प्रभारी और ज़मिमेदार व्यक्ति।
- ऐच्छिक डफिल्टरस की पहचान:**
  - ऐच्छिक डफिल्टरस के सबूत की जाँच ऋणदाता द्वारा गठित एक पहचान समिति (जिसमें अध्यक्ष के रूप में पूरणकालिक नदिशक और दो वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे) द्वारा की जाएगी।
  - यदि समिति इस बात से संतुष्ट है कि चूक जान-बूझकर की गई है, तो वह उधारकर्त्ता को कारण बताओ नोटिस जारी करेगी।
- ऐच्छिक डफिल्टरस के खिलाफ उपाय:**
  - आवश्यकता पड़ने पर ऋणदाता जान-बूझकर चूक करने वालों के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही शुरू कर सकते हैं। जान-बूझकर चूक करने वाले पुनः ऋण सुवधि के लिये पात्र नहीं होंगे।

## गृह मामले

### जेलों की स्थिति, इंफ्रास्ट्रक्चर और सुधारों पर स्थायी समिति की रिपोर्ट

गृह मामलों से संबंधित स्थायी समिति ने 'जेलों की स्थिति, इंफ्रास्ट्रक्चर और सुधार' पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। समिति के मुख्य नषिकर्षों एवं सुझावों में नमिनलखिति शामिल है:

- ओवरक्राउडिंग:** समिति ने कहा कि जब जेलों में बहुत अधिक कैदी होते हैं तो उसका कैदियों के साथ-साथ आपराधिक न्याय प्रणाली पर भी गंभीर परिणाम होता है। भारत भर की जेलों में राष्ट्रीय स्तर पर ऑक्यूपेंसी की औसत दर 130% है। उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश सहित छह राज्यों में कैदियों की कूल आबादी का आधे से अधिक हिस्सा है। इन छह राज्यों में से चार में ऑक्यूपेंसी दर राष्ट्रीय औसत से अधिक है। समिति ने सुझाव दिया कि समझौता ज्वापन पर दस्तखत करके कैदियों को ओवरक्राउडेड जेलों से उसी राज्य की या किसी दूसरे राज्य की जेलों में स्थानांतरित किया जाए।
- कशोर अपराधी:**
  - समिति ने कहा कि युवा अपराधी की परिभाषा को लेकर सभी राज्यों में स्पष्टता का अभाव है।
  - इसने गृह मंत्रालय से सभी राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को एक सामान्य दशा-नरिदेश के साथ कशोर अपराधियों की स्पष्ट परिभाषा प्रदान करने की सफिराशि की।
- महिला कैदी:**
  - समिति ने गर्भवती महिलाओं पर वशिष ध्यान देने का सुझाव दिया, जिसमें जेल के बाहर बच्चे को जन्म देने की क्षमता और उचित प्रसवपूर्व तथा प्रसवोत्तर देखभाल शामिल है।
  - बच्चों का पालन-पोषण सुनिश्चित करने हेतु समिति ने जेल में पैदा हुए बच्चों को 12 वर्ष की उमर तक अपनी माँ के साथ रहने की अनुमति देने की सफिराशि की।

## उपभोक्ता मामले

### ई-कॉमर्स में डार्क पैटर्न को वनियमिति करने हेतु दशा-नरिदेश

उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय ने [डार्क पैटर्न](#) की रोकथाम और वनियमिति, 2023 के लिये मसौदा दशा-नरिदेशों पर टपिपणयिँ आमंत्रित की हैं।

- डार्क पैटर्न, प्लेटफॉर्मों के यूजर इंटरफेस (UI) में ऐसी पद्धतियों या भ्रामक डिज़ाइन पैटर्न को कहा जाता है जो उपयोगकर्ताओं को अनपेक्षित कार्यों को करने हेतु गुमराह करने या धोखा देने के लिये डिज़ाइन किया गया हो।
- ये पैटर्न उपभोक्ता की स्वायत्तता, नरिणय या पसंद को प्रभावित करते हैं और भ्रामक या अनुचित व्यापार पद्धतियों के समान होते हैं।

मसौदा दशा-नरिदेशों की मुख्य वशिषताओं में नमिनलखिति शामिल हैं:

- **डार्क पैटर्न में शामिल होने पर प्रतबिंध:**
  - ये मसौदा दशा-नरिदेश भारत में वस्तुओं या सेवाएँ प्रदान करने वाले सभी प्लेटफॉर्म, वजिजापनदाताओं और वकिरेताओं पर लागू होंगे।
- उपभोक्ता संरक्षण अधनियम, 2019 के तहत स्थापति केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) डार्क पैटर्न की व्याख्या से संबंधित अस्पष्टताओं या वविदाओं को नपिटाने के लिये जमिमेदार होगा।
  - अधनियम के तहत CCPA के नरिदेशों का पालन न करने पर छह महीने तक की कैद, 20 लाख रुपए तक का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं।

## परविहन

### स्थायी समति द्वारा राष्ट्रीय अंतरदेशीय जलमार्ग पर रपिोर्ट प्रस्तुत

- अंतरदेशीय जलमार्ग एक नौगमय नदी और नहर प्रणाली है। भारतीय अंतरदेशीय जलमार्ग प्राधिकरण (IWAI) अंतरदेशीय शपिगि और नेवगिशन के लिये राष्ट्रीय जलमार्गों को वनियमति तथा वकिसति करता है।

समति के प्रमुख नषिकर्षों और सुझावों में नमिनलखिति शामिल हैं:

- **राष्ट्रीय जलमार्गों का परचालन:**
  - देश में 111 अधसूचित राष्ट्रीय जलमार्ग हैं जिनमें से 23 को चालू कर दिया गया है।
  - बंदरगाह, जहाज़रानी और जलमार्ग मंत्रालय ने कहा है कि वित्तीय एवं कर्मचारियों की कमी के कारण 63 राष्ट्रीय जलमार्गों का वकिस नही किया जा रहा है।
  - समति ने सुझाव दिया कि फलिहाल इन 63 जलमार्गों का वकिस न किया जाए क्योंकि ये अवावहारकि है।
- **कार्गो के परविहन के लिये इंटरमॉडल कनेक्टविटी:** समति ने कहा कि प्रमुख बंदरगाहों, रेल और सड़कों के साथ जलमार्गों की कनेक्टविटी से कार्गो के परविहन का बोझ कम होने के साथ ही लॉजिस्टिक्स की लागत में कमी आएगी।
- समति ने सुझाव दिया कि नए अधसूचित जलमार्गों के मामले में रेल, सड़क और बंदरगाहों के साथ कनेक्टविटी के कार्य को परयोजना के चरण में ही नपिटया जाना चाहिये।
- **जलमार्गों की कम हसिसेदारी:** भारत में माल ढुलाई में जलमार्गों की औसत हसिसेदारी लगभग 2% है, जबकि USA में यह आँकड़ा 4%, चीन में 14%, वयितनाम में 48% और नीदरलैंड्स में 49% है।
- भारत का लक्ष्य वर्ष 2030 तक इस क्षेत्र की हसिसेदारी को 5% तक बढ़ाना है।
- समति ने सुझाव दिया कि मंत्रालय एक कार्य योजना बनाए ताकि स्थायी पारगमन वकिल्प और पर्यटन सेवा के रूप में जलमार्गों की क्षमता का दोहन किया जा सके।

### भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम (Bharat NCAP)

- सड़क परविहन और राजमार्ग मंत्रालय ने **केंद्रीय मोटर वाहन नयिम, 1989** में संशोधन अधसूचित किये हैं। नयिम मोटर वाहन अधनियम, 1988 के प्रावधानों के तहत बनाए गए हैं।
- संशोधनों में एम1 श्रेणी के तहत वाहनों की सुरक्षा रेटिंग का आकलन करने के लिये भारत न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम (Bharat NCAP) की शुरुआत की गई है।
  - M1 श्रेणी में 3.5 टन तक वजन वाली कारें शामिल हैं जो आठ यात्रियों (ड्राइवर को छोड़कर) को ले जा सकती हैं।
  - ऑटोमोटिव इंडस्ट्री स्टैंडर्ड (AIS) 197 के अनुसार स्टार रेटिंग के लिये वाहनों की जाँच और मूल्यांकन किया जाएगा।
  - ड्राफ्ट AIS 197 (अभी तक अधसूचित नहीं किया गया) के अनुसार, समग्र वाहन सुरक्षा मूल्यांकन इस पर आधारित होगा:
    - बालगि यात्रियों की सुरक्षा।
    - नाबालगि यात्रियों की सुरक्षा।
    - सुरक्षा सहायता प्रौद्योगिकियाँ।

यह कार्यक्रम वाहनों के लिये 1 अक्टूबर, 2023 से लागू होगा।

### फटिनेस प्रमाणपत्र की वैधता

- नयिम मोटर वाहन अधनियम, 1988 के प्रावधानों के तहत तैयार किये गए हैं। 1988 का अधनियम केंद्र सरकार को परविहन वाहनों के लिये फटिनेस प्रमाणपत्र जारी करने हेतु नयिम नरिधारति करने का अधिकार देता है।
- फटिनेस प्रमाणपत्र इस बात का प्रमाण है कि वाहन सुरक्षित है और सड़क पर उपयोग के लिये उपयुक्त है।
- **नए नयिम अधसूचित:**

- 1989 के नियमों के तहत पुराने परविहन वाहनों के लिये फटिनेस प्रमाणपत्र की वैधता एक वर्ष थी।
  - संशोधनों ने आठ वर्ष तक पुराने वाहनों के लिये वैधता अवधि को दो वर्ष तक बढ़ा दिया है।
  - केवल स्वचालित परीक्षण स्टेशनों को नमिनलखिति के लिये फटिनेस प्रमाणपत्र जारी करना चाहिये।
    - भारी माल वाहन
    - भारी यात्री मोटर वाहन
    - मध्यम माल वाहन
    - हल्के मोटर
- नए नियम 1 अक्टूबर, 2024 से लागू होंगे।

## पर्यटन

### भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण की कार्य प्रणाली पर रिपोर्ट

- अंतरदेशीय जलमार्ग एक नौगम्य नदी और नहर प्रणाली है। [भारतीय अंतरदेशीय जलमार्ग प्राधिकरण \(IWAI\)](#) अंतरदेशीय शपिगि एवं नेविगेशन के लिये राष्ट्रीय जलमार्गों को वनियमिति तथा वकिसिति करता है।
- समिति की प्रमुख टपिपणयिं और सफिरशिं में नमिनलखिति शामिल हैं:
  - समिति ने सफिरशि की कइिन स्मारकों की सूची को राष्ट्रीय महत्त्व, अद्वितीय वास्तुशलिप मूल्य और वशिषिट वरिसत सामग्री के आधार पर तर्कसंगत बनाया जाए।
  - इसने भारतीय पुरातत्त्व सर्वेक्षण (Archaeological Survey of India- ASI) को उसके द्वारा बनाए गए सभी स्मारकों की भौतिक सुरक्षा सुनिश्चित करने की सफिरशि की और सुरक्षा सुनिश्चित करने में कर्मियों की कमी को एक प्रमुख बाधामाना।

#### स्मारकों के आस-पास प्रतबिंधित क्षेत्र:

- पुरातत्त्वक स्थलों के 300 मीटर के दायरे में नरिमाण और खनन सहित विभिन्न गतिविधियिं कानून के तहत प्रतबिंधित हैं।
- समिति ने कहा कि इसके कारण सार्वजनिक स्तर पर आलोचना होती है और असुवधि की स्थिति पैदा होती है क्योंकि कुछ मामलों में एक पूरा गाँव इस दायरे में आता है। समिति ने सुझाव दिया कि इन प्रतबिंधितों को तर्कसंगत बनाया जाना चाहिये।

### वशिषिट पर्यटन और संभावित पर्यटन स्थलों के विकास पर स्थायी समिति की रिपोर्ट

- वशिषिट पर्यटन समान रुचियिं वाले लोगों के छोटे समूहों की जरूरतों को पूरा करता है। इसमें ग्रामीण पर्यटन, साहसिक पर्यटन, इको-पर्यटन और चकितिसा पर्यटन शामिल हैं।
- **ग्रामीण पर्यटन:**
  - समिति ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन द्वारा तैयार सर्वोत्तम पर्यटन गाँवों की सूची में कोई भी भारतीय गाँव शामिल नहीं है।
  - उसने कहा कि ग्रामीण पर्यटन में ग्रामीणों के लिये रोजगार और आय बढ़ाने की अपार संभावनाएँ हैं।
  - उसने सुझाव दिया कि ग्रामीण पर्यटन संबंधी वेबसाइट को ग्रामीण होमस्टे, यात्रा कनेक्टिविटी और गाँवों में पर्यटन स्थलों का वविरण प्रदान करना चाहिये।
- **साहसिक पर्यटन:**
  - समिति ने कहा कि साहसिक खेलों में दुर्घटनाओं की संख्या में वृद्धि हुई है।
  - उसने बना लाइसेंस वाले साहसिक टूर ऑपरेटरों की उपस्थिति का भी उल्लेख किया।
  - समिति ने कहा कि पर्यटन मंत्रालय को एक कानून बनाना चाहिये ताकि केवल लाइसेंस प्राप्त ऑपरेटर ही साहसिक पर्यटन सेवाएँ प्रदान करें।
- **चकितिसा पर्यटन:**
  - समिति ने कहा कि चकितिसा पर्यटन क्षेत्र में नियमों की कमी है, इसलिये सेवाओं की गुणवत्ता की नगिरानी नहीं हो पाती।
  - उसने सभी चकितिसा पर्यटन सुवधि प्रदाताओं को अनविर्य रूप से सरकार के साथ पंजीकरण करने का सुझाव दिया।
  - उसने मंत्रालय को सुझाव दिया कि वह अस्पतालों को संयुक्त आयोग की अंतरराष्ट्रीय मान्यता प्राप्त करने के लिये प्रोत्साहित करे क्योंकि इसे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त है।
- **स्वदेश दर्शन योजना:**
  - योजना के तहत 15 वषियगत सर्कटों की पहचान की गई है।
  - पर्यटन अवसंरचना के विकास के लिये 31 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में 76 परियोजनाएँ स्वीकृत की गई हैं। समिति ने कहा कि मंदिर या वन अधिकारियों से मंजूरी मलिनने में देरी के कारण कई परियोजनाओं को शुरू करने में देरी हो रही है।
  - इसने परियोजनाओं की वास्तविक समय (रयिल टाइम) की नगिरानी का सुझाव दिया।

## ऊर्जा

### ऊर्जा भंडारण प्रणालियों को बढ़ावा देने हेतु रूपरेखा जारी

- भारत का लक्ष्य वर्ष 2030 तक गैर-जीवाश्म ऊर्जा स्रोतों से 50% संचयी स्थापित क्षमता प्राप्त करना है। इस पैमाने पर अक्षय ऊर्जा क्षमता के एकीकरण के लिये ऊर्जा भंडारण प्रणालियाँ महत्त्वपूर्ण होंगी।
- फ्रेमवर्क में नमिनलखिति प्रमुख उपायों का सुझाव दिया गया है:
  - नयामक उपाय:
    - ऊर्जा भंडारण प्रणालियों की वित्तीय और वाणज्यिक व्यवहार्यता सुनिश्चित करने के लिये कुछ नयामक उपाय प्रस्तावित किये गए हैं।
  - इनमें नमिनलखिति शामिल हैं:
    - ऊर्जा भंडारण प्रणालियों को प्रोत्साहित करने के लिये बजिली खरीद दशा-नरिदेश तैयार करना,
    - कार्बन क्रेडिट के साथ ऊर्जा भंडारण प्रणाली प्रदान करना जहाँ वे चार्जिंग के लिये अक्षय ऊर्जा का उपयोग करते हैं।
    - 5 मेगावाट से अधिक की नई अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं को अपनी अक्षय ऊर्जा क्षमता के कम-से-कम 5% के लिये ऊर्जा भंडारण प्रणाली स्थापित करनी होगी।
- वित्तीय प्रोत्साहन:
  - बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणालियों के लिये पूंजीगत लागत का 40% तक वायबलिटी गैप फंडिंग प्रदान किया जाना चाहिये (बशर्ते कि परियोजना 18-24 महीनों के भीतर चालू हो)।
  - ऊर्जा भंडारण प्रणालियों और सहायक घटकों के घरेलू वनिर्माण को प्रोत्साहित करने के लिये PLI योजना तैयार की जानी चाहिये।
- टेक्नोलॉजी-एगनॉस्टिक नीलामी:
  - परियोजनाओं के लिये प्रतस्पर्द्धी बोली दशा-नरिदेशों में कुछ प्रौद्योगिकियों को प्राथमिकता नहीं दी जानी चाहिये।
- पुनर्र्चरण और स्थरिता:
  - सभी नीलामी दस्तावेजों में एंड-टू-लाइफ प्रबंधन योजना लागू नहीं होनी चाहिये। इन योजनाओं को पुरानी बैटरियों को दोबारा इस्तेमाल करने (रीपरपज़गि या रीयूज़गि) के लिये प्रोत्साहित किया जाना चाहिये।

## कैप्टवि बजिली उत्पादकों और उपयोगकर्त्ता संबंधी नयिमों में संशोधन

- कैप्टवि उत्पादन संयंत्र एक ऐसा बजिली संयंत्र होता है जो खुद के उपयोग के लिये स्थापित किया जाता है। संशोधनों में कुछ कैप्टवि उत्पादन संयंत्रों के सत्यापन के लिये कहा गया है और कैप्टवि उपयोगकर्त्ताओं की परभाषा में बदलाव किया गया है। संशोधित नयिमों की मुख्य वशिषताओं में नमिनलखिति शामिल हैं:
- कैप्टवि उपयोगकर्त्ताओं की परभाषा में बदलाव:
  - संशोधन कैप्टवि उपयोगकर्त्ता मानी जाने वाली संस्थाओं के दायरे को वसितृत करते हैं। पहले, नयिमों में नरिदषिट किया गया था कि संबद्ध कंपनियों (जसिमें कैप्टवि उपयोगकर्त्ता के पास कम-से-कम 51% स्वामतिव था) को कैप्टवि उपयोगकर्त्ता माना जाएगा।
  - संशोधित नयिमों में संबद्ध कंपनी शब्द को होलडगि कंपनी से बदल दिया गया है जसि कंपनी अधनियिम, 2013 में परभाषित किया गया है।
- कुछ कैप्टवि उत्पादक संयंत्रों का सत्यापन:
  - संशोधन में यह कहा गया है कि कुछ उत्पादन संयंत्रों की कैप्टवि स्थिति को केंद्रीय बजिली प्राधकिरण द्वारा सत्यापित किया जाएगा।
  - यह केवल उन उत्पादन संयंत्रों पर लागू होता है जनिमें कैप्टवि उपयोगकर्त्ता और उसके कैप्टवि उत्पादन संयंत्र एक से अधिक राज्यों में स्थित हैं।

## खनन

### खनन लीज़ और कंपोज़िट लाइसेंस की नीलामी के नयिमों में संशोधन

- खान मंत्रालय ने खनजि (नीलामी) नयिम, 2015 में संशोधन अधसिचति किये हैं। नयिम खान और खनजि (वकिस एवं वनियिमन) अधनियिम, 1957 के तहत तैयार किये गए हैं।
- यह अधनियिम भारत में खनन क्षेत्र को नरिचरति करता है। वर्ष 2015 के नयिम खानों की नीलामी आयोजति करने की प्रक्रिया नरिधारति करते हैं।

संशोधित नयिमों की मुख्य वशिषताओं में नमिनलखिति शामिल हैं:

- महत्त्वपूर्ण और रणनीतिक खनजि के लिये रियायतें:
  - संशोधित नयिम महत्त्वपूर्ण और रणनीतिक खनजि के लिये रियायतों के संबंध में राज्य सरकार हेतु कुछ शर्तें प्रस्तुत करते हैं। ये खनजि अधनियिम की पहली अनुसूची में नरिदषिट हैं और इसमें लथियिम युक्त खनजि और ग्रेफाइट शामिल हैं।
- भूमिका वर्गीकरण:
  - वर्ष 2015 के नयिमों के तहत राज्य सरकार स्थापित खनजि सामग्री वाले क्षेत्र में खनन लीज़ देने के लिये नीलामी करा सकती है।
  - नीलामी से पहले राज्य सरकार को सर्वेक्षण उपकरणों का उपयोग करके क्षेत्र की पहचान और उसे चहिनति करना होगा। क्षेत्र को इस प्रकार वर्गीकृत किया जाना चाहिये:
    - वन भूमि
    - राज्य सरकार के स्वामतिव वाली भूमि
    - ऐसी भूमि जो राज्य सरकार के स्वामतिव वाली नहीं है।
    - संशोधित नयिमों में प्रावधान है कि इस उद्देश्य के लिये राज्य सरकारें नमिनलखिति में उपलब्ध भूमिविवरण का उपयोग कर सकती हैं:



- प्रधानमंत्री गतशिक्षा पोर्टल ।
- राज्य सरकार का भूमि रिकॉर्ड पोर्टल ।
- किसी अन्य सरकारी प्राधिकरण का रिकॉर्ड ।

## पर्यावरण

### वसितारति नरिमाता उत्तरदायतिव नयिम अधसिचति

- नयिम पर्यावरण संरक्षण अधनियम, 1986 के तहत बनाए गए हैं । ये नयिम खतरनाक अपशषिट उत्पादन को कम करने और पुनरचकरण के उपाय करने के लयि बनाए गए थे ।
- परयुक्त तेल के प्रबंधन के लयि संशोधन को **वसितारति उत्पादक जमिमेदारी (EPR)** को जोड़ा गया है, जसिके लयि उत्पादकों को ऐसे परयुक्त तेल की रीसाइकलिंग करनी होगी ।
  - परयुक्त तेल का तातपरय कचचे तेल या सथिटकि तेल युक्त मशिरण से प्रापत तेल और रीप्रोसेसिंग के लयि उपयुक्त तेल से है ।
  - EPR उन उत्पादकों पर लागू होता है जो बेस ऑयल/लुबरकिशन ऑयल का नरिमाण करते और/या उसे बेचते हैं ।

संशोधनों की मुख्य वशिषताओं में नमिनलखिति शामिल हैं:

- **परयुक्त तेल का प्रबंधन:**
  - संशोधति नयिमों के अनुसार, परयुक्त तेल का प्रबंधन नमिनलखिति के माध्यम से कयि जाएगा:
    - री-रफाइंड बेस ऑयल/लुबरकिशन ऑयल का उत्पादन
    - ऊर्जा रकिवरी यानी परयुक्त तेल को ईधन के रूप में उपयोग करना ।
- **EPR लक्ष्य:**
  - अब यह नरिमाता की जमिमेदारी है कि वह परयुक्त तेल का पर्यावरण के अनुकूल प्रबंधन सुनिश्चति करने के लयि पंजीकृत पुनरचकरणकर्त्ताओं के माध्यम से परयुक्त तेल को पुनरचकरण करे ।
  - नयिम इन दायतिवों को पूरा करने के लयि बेस ऑयल/लुबरकिशन ऑयल की वार्षकि बकिरी/आयात के आधार पर लक्ष्य नरिदषिट करते हैं ।
  - लक्ष्य पूरा करने के लयि नरिमाता डीलर जैसे तीसरे पक्ष के संगठनों की मदद ले सकते हैं । केवल री-रफाइनिंग के लयि परयुक्त तेल के आयात की अनुमति है ।
- **नरिमाता उत्तरदायतिव प्रमाणपत्र:**
  - नरिमाता परयुक्त तेल के पंजीकृत पुनरचकरणकर्त्ताओं से प्रमाणपत्र खरीदकर अपने EPR को पूरा कर सकते हैं ।
    - पुनरचकरण का तातपरय परयुक्त तेल को पुनः परिष्कृत करना या परयुक्त तेल से ऊर्जा पुनरप्रापति करना है । नरिमाता की वर्तमान और पछिले वर्षों की देनदारी के आधार पर भी प्रमाणपत्र खरीदे जा सकते हैं ।
- **पंजीकरण:**
  - संशोधनों में उत्पादकों, कलेक्शन एजेंटों, पुनरचकरणकर्त्ताओं और परयुक्त तेल के आयातकों को **केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB)** में पंजीकरण करने का आदेश दयिा गया है ।
- **अनुपालन सुनिश्चति करना:** दायतिवों को पूरा न करने की स्थिति में CPCB द्वारा पर्यावरणीय मुआवजा लगाया जा सकता है ।
- झूठी जानकारी प्रस्तुत करने के लयि संस्थाओं पर मुकदमा चलाया जा सकता है । नयिम कार्यान्वयन की नगिरानी हेतु CPCB अध्यक्ष की अध्यक्षता में एक संचालन समिति स्थापति करने का प्रावधान करते हैं ।

## शकिषा

### उच्च शकिषा में NEP के कार्यान्वयन पर रिपोर्ट

**राष्ट्रीय शकिषा नीति (NEP), 2020** भारत की शकिषा प्रणाली की संरचना और उद्देश्यों में संशोधन की रूपरेखा तैयार करती है । इनमें स्कूल प्रणाली के लयि पाँच-चरणीय डिजाइन शुरू करना और बहु-वषिक शकिषा को प्रोत्साहति करना शामिल है ।

समिति के नषिकर्षों और सुझावों में नमिनलखिति शामिल हैं:

- **अंतरवषिक और व्यक्तगित शकिषण:**
  - इसमें जममू वशिषवदियालय द्वारा शुरू कयि गए 'डिजाइन योर डिग्री' प्रोग्राम का उल्लेख कयिा गया है, जो NEP में उल्लखिति च्वाइस-बेसड करेडिट सिस्टम पर आधारति है ।
  - प्रोग्राम वदियार्थियों को अंतरवषिक और व्यक्तगित शकिषण का विकल्प प्रदान करता है । समिति ने इस प्रोग्राम को अन्य संस्थानों में शुरू करने का सुझाव दयिा ।
- **डजिटल लाइब्रेरी:**
  - समिति ने कहा कि डिजिटल लाइब्रेरी वदियार्थियों और शकिषकों को सीखने हेतु संसाधनों की एक वसितृत शृंखला तक सुवधाजनक पहुँच प्रदान कर सकती है ।
  - इसने उच्च शकिषा वभिाग को बेहतर पहुँच और सीखने के परिणामों के लयि कषेत्रीय भाषाओं में सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चति करने का सुझाव दयिा ।
- **हाशयि पर रहने वाले वदियार्थी:**

- समतिने वर्ष 2016-17 से वर्ष 2020-21 के बीच SC और ST समुदायों के वदियार्थियों के सकल नामांकन अनुपात (GER) और समग्र GER के बीच अंतर पर ध्यान दिया ।
- समतिने इन समुदायों के वदियार्थियों के लिये उच्च शिक्षा पहुँच को और बेहतर बनाने के लिये वशिष्ट उपायों का सुझाव दिया ।

इनमें नमिनलखिति शामिल हैं:

- लक्षति जागरूकता अभियान चलाना ।
- दूरदराज के क्षेत्रों और शहरी सलमस बस्तियों में बुनयिादी ढाँचे का वकिस करना ।
- हाशयि पर रहने वाले समुदायों के बीच काम करने वाले शकिषकों को वशिष प्रशकिषण प्रदान करना ।
- हाशयि पर रहने वाले समुदायों की आवशयकताओं के अनुरूप छातरवृत्ततिप्रदान करना ।
- इसने शकिषकों के लिये एक पारदर्शी और कुशल भरती प्रकरयिा स्थापति करने का भी सुझाव दिया जो वविधिता को प्राथमकिता देती है ।

## श्रम एवं रोजगार

### स्थायी समतिने कर्मचारी राज्य बीमा नगिम पर रपिोर्ट प्रस्तुत की

- 'कर्मचारी राज्य बीमा अधनियिम, 1948 नयिकताओं को यह आदेश देता है कविह बीमति वयक्तियों की चकितिसा देखभाल में योगदान करे ।
- यह कानून न्यूनतम 10 वयक्तियों को रोजगार देने वाले कारखानों पर लागू होता है । केंद्र और राज्य सरकारें दुकानों, होटलों, सनिमाघरों, न्यूजपेपर इस्टैबलशिमेंट्स और पोर्ट ट्रस्ट्स को भी उसके दायरे में शामिल करता है ।
- यह कानून **कर्मचारी राज्य बीमा नगिम (ESIC)** और **कर्मचारी राज्य बीमा योजना (ESI योजना)** की स्थापना करता है ।

प्रमुख नषिकर्षों और सुझावों में नमिनलखिति शामिल हैं:

- **ESI योजना के तहत कवरेज हेतु वेतन सीमा में संशोधन:**
  - समतिने कहा क अंशदान का भुगतान करने से छूट वाली वेतन सीमा पछिले सात वर्षों से अपरविरतनीय बनी हुई है, इसके बावजूद कसिमय के साथ वेतन में बढोतरी हुई है ।
  - वर्तमान में 176 रुपए प्रतदिनि की वेतन सीमा पर छूट लागू है, जो काफी कम है ।
  - समतिने सुझाव दिया क श्रम एवं रोजगार मंत्रालय को कवरेज, अंशदान और वेतन की पात्रता से संबंधति प्रावधानों में संशोधन करना चाहयि ।
- **योजना के कवरेज का वसितार:**
  - ESI अधनियिम, 1948 को सामाजकि सुरक्षा संहति, 2020 में शामिल कया गया है । समतिने कहा कसंहति के कारयान्वयन के साथ ESI के कवरेज में नमिनलखिति शामिल होंगे:
    - 10 से कम वयक्तियों वाले प्रतषिठानों का स्वैच्छकि कवरेज ।
    - खतरनाक वयवसाय में लगे प्रतषिठानों के लिये अनविरय कवरेज ।
    - असंगठति श्रमकिों, गगि वर्कर्स और प्लेटफॉर्म वर्कर्स के लिये वशिष योजनाएँ बनाने हेतु प्रावधान ।
    - समतिने कहा क मंत्रालय और ESI कवरेज बढाने के लिये तत्पर नहीं है ।
    - बीमा के पात्र वयक्तियों की पहचान करने के लिये वयापक सर्वेक्षण, डेटा कलेक्शन और आधार नामांकन का उपयोग कया जाए ताकसंहति को सुचारु रूप से लागू कया जा सके ।